प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में जीवीके समूह के रैटल पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी 850 मेगावाट की परियोजना पर 5,500 करोड़ रुपए का खर्च

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाए जाने वाले जीवीके समूह के 850 मेगावाट पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी।

जीवीके को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 5,500 करोड़ रूपए की इस परियोजना को पूरा करने का ठेका दिया या। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों से 14,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की क्षमता है।

जीवीके समूह के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जीवीके रेड्डी ने कहा कि "इस परियोजना के जरिए हम इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना चाहते हैं जिससे लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा।"

रैटल परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए जीवीके समूह 262 करोड़ रूपए व्यय कर रहा है। इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय सहित बाकी मंजूरियां मिल चुकी हैं ।

विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के लिए काम करने वाली हैदराबाद स्थित यह कंपनी इससे पहले पर्यावरण सहित विभिन्न नियामक मंजूरी ले चुकी है। इसने निर्माण क्षेत्र में प्रमुख एलएंडटी को निर्माण का काम दिया है। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में द्रबशाला गांव के निकट चेनाब नदी पर शुरू की जाएगी। यह दुल्हस्ती (390 मेगावाट) की ऊर्ध्वप्रवाह और बालिहार (450+450 मेगावाट) अनुप्रवाह के बीच है।

आगे की दिशा

- जीवीके ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से यह परियोजना हासिल की।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए इसने 262 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।
- निर्माण का ठेका एलएंडटी को दिया गया है।
- परियोजना को चेनाब नदी पर लगाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा जीवीके को यह परियोजना दी गई। टैरिफ-आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई यह राज्य की पहली पनबिजली परियोजना है।

परियोजना के तहत गहरे भूमिगत बिजली घर के साथ 195 मीटर लंबे और 133 मीटर उंचे बांध का निर्माण किया । जिसमें 205 मेगावाट प्रत्येक की चार उत्पादक यूनिट के साथ 30 मेगावाट यूनिट अतिरिक्त जलधारा के इस्तेमाल की क्षमता होगी।

जम्मू -कश्मीर राज्य को 16 प्रतिशत बिजली नि:शुल्क मिलेगी। विद्युत संयंत्र के संचालन के 35 वर्षों के बाद इसे राज्य को वापस दे दिया जाएगा।

(स्रोत-एजेंसियां)